

आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 05.12.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :-

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांवों में क्लस्टर बनाकर हर्बल क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से कार्य किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
- सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा— सहकारिता मेलों के आयोजन का उद्देश्य समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर पांच दशमलव दो-पांच प्रतिशत किया।
- चम्पावत जिले के लोहाघाट में किसानों को कीवी उत्पादन के लिए मिट्टी परीक्षण, पौधरोपण और रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांवों में क्लस्टर बनाकर हर्बल क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से कार्य किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उपलब्ध हर्बल और औषधीय उत्पादों के संवर्धन व प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। आज सचिवालय में आयोजित जड़ी-बूटी सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने जड़ी-बूटी और एरोमा क्षेत्र में अग्रणी दो राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन करने के लिए राज्य से विषय विशेषज्ञों की टीम भेजने के निर्देश दिए, जिससे उत्तराखंड में भी इन नवाचारों को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि जड़ी-बूटी क्षेत्र में टर्नओवर बढ़ाने के लिए अनुसंधान, नवाचार, उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग पर समन्वित रूप से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक हर्बल संपदा का केंद्र है। राज्य में इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए हर्बल अर्थव्यवस्था को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का अधिकतम लाभ दिलाने, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिकी से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में भालू और अन्य जंगली जीवों से जन-जीवन और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, वहां कृषि और वन विभागों की संयुक्त टीमों भेजी जाएं। ये टीमों लोगों को सुरक्षा उपायों और फसल संरक्षण के लिए जानकारी देंगी।

सहकारिता मेला

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में सहकारिता मेलों के आयोजन का उद्देश्य समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। डॉ. रावत आज हरिद्वार में आयोजित सहकारिता मेले में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और महिला समूह के उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और कई उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दस जिलों में इन मेलों का आयोजन हो चुका है, जबकि अन्य तीन जिलों में भी इनका आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

डॉ. रावत ने मेले में दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत चेक और माइक्रो एटीएम वितरित करने के साथ ही वित्तपोषित उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया।

राज्यपाल भेंट

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज लोकभवन में परिवीक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां विशिष्ट हैं, जहां दूरस्थ और कठिन इलाकों में सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है। अधिकारियों को इन चुनौतियों को समझते हुए सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह अधिकारियों का मिशन और विजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, ईमानदारी और समयबद्धता अपना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने का संकल्प लेने का आग्रह किया। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षु अधिकारी अपनी सकारात्मक सोच, कार्यनिष्ठा और सेवा भावना से उत्तराखण्ड को नई दिशा देंगे।

मौद्रिक नीति

भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए आज ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 5 दशमलव दो-पांच प्रतिशत कर दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति में इस निर्णय की घोषणा की।

इससे आवास, ऑटो और वाणिज्यिक सहित विभिन्न ऋण सस्ते होने की उम्मीद है। यह कटौती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के पिछले तीन महीनों से सरकार द्वारा निर्धारित 2 प्रतिशत के निचले स्तर से नीचे रहने के मद्देनजर की गई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि इस वर्ष की पहली छमाही में दो दशमलव दो प्रतिशत की सौम्य मुद्रास्फीति और आठ प्रतिशत की वृद्धि दर एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स काल का संकेत देती है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6 दशमलव 8 प्रतिशत के पहले के विकास अनुमान को बढ़ाकर 7 दशमलव 3 प्रतिशत कर दिया है।

कीवी प्रशिक्षण

चम्पावत जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सुई, लोहाघाट में कीवी उत्पादन पर आज किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. आर.के. शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य समूह के माध्यम से लोगों को कीवी उत्पादन और विपणन का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ना है।

उद्यान वैज्ञानिक डॉ. रजनी पन्त ने बताया कि किसानों को मिट्टी के परीक्षण, पौधरोपण और रख-रखाव आदि के बारे में भौतिक और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण व जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि चम्पावत जिले की जलवायु कीवी के लिए उपयुक्त होने के कारण यहां छह प्रजातियों का उत्पादन हो रहा, जिसमें एलिसन और हेवर्ड प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कीवी उत्पादन, भविष्य में रिवर्स पलायन का मजबूत आधार बनेगा।

खेल मंत्री

खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज पिथौरागढ़ के मुवानी में शेर सिंह कार्की मेमोरियल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी हिस्सों से ग्रामीण अंचल की टीमों हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्र में भी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य यह है कि प्रदेश के हर गांव से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के चैंपियन निकलें, तभी उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने का सरकार का सपना साकार हो सकेगा। इस अवसर पर खेल मंत्री ने निर्माणाधीन खेल मैदान का निरीक्षण भी किया और कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

ईवीएम निरीक्षण

पौड़ी की जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने डबल लॉक प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन सुरक्षा, और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती सहित संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि वेयरहाउस में स्थापित सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह क्रियाशील रहें और तैनात पुलिस बल सुरक्षा उपकरणों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा प्रणाली और संरचना की विस्तृत जानकारी भी दी।